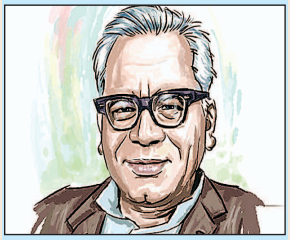
ताल-बेताला



शशिकांत गुप्ते,
मोबाइल नं.
78984-88217

निराशा के कर्तव्य



प्रखर समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया ने निराशा और हार को लेकर एक बेहद मौलिक और ऐतिहासिक विचार दिया था, जिसे 'निराशा के कर्तव्य' कहा जाता है। 23 जून 1962 को नैनीताल में दिए अपने एक ऐतिहासिक व्याख्यान में उन्होंने इस दर्शन को सामने रखा था। लोहिया जी का मानना था कि जब चारों तरफ अन्याय,असफलता और निराशा का माहौल हो, तब भी व्यक्ति को हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए।

लोहिया जी ने निराशा को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा था।

1)राष्ट्रीय निराशा उन्होंने चिंता व्यक्त की कि पिछले 1500 वर्षों में भारत की आम जनता ने देश के भीतर के आततायियों या आंतरिक सामाजिक अन्यायों (जैसे जाति प्रथा और गैर-बराबरी) के खिलाफ कभी बड़ा सामूहिक विद्रोह नहीं किया। जनता अन्यायों को नियति मानकर स्वीकार कर लेती है।

2)अंतरराष्ट्रीय निराशा:

पश्चिमी देशों की तकनीकी बढ़त,दिमागी साम्राज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी आर्थिक गैर-बराबरी के खिलाफ कोई बड़ी वैश्विक बगावत न होना।

3)मानवीय निराशा

समाज में न्याय और अन्याय के बीच चलने वाली लड़ाई में जब न्याय कमजोर दिखने लगे और चारों तरफ हार का माहौल हो।

डॉ. लोहिया का कहना था कि 'निराशा ही वह कर्तव्य है जो व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है।' उनका दर्शन यह था कि यदि आपको चारों तरफ अंधकार या असफलता (निराशा) भी दिखे, तब भी न्याय और समता के लिए लड़ना आपका कर्तव्य है। परिणाम चाहे जो हो, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सिद्धांत एक हताश कौम या समाज में नई हिम्मत और ऊर्जा फूंकने का काम करता है।

डॉ.लोहियाजी द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त विचारों को प्रकट करना आज प्रासंगिक है।

संभवतः आज विपक्ष जो भूमिका अदा कर रहा है,इसे 'निराशा के कर्तव्य' ही कहा जाएगा। बार बार यह स्पष्ट करना पड़ रहा है कि विपक्ष का मतलब सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं होता है। विपक्ष का व्यापक अर्थ है,विपक्षी दल या समूह या कोई एक अकेला व्यक्ति भी सत्ता की जनविरोधी नीतियों का विरोध करता है वह विपक्ष ही कहलाएगा।

सन 2014 से 2019 तक थोड़ी हताशा जरूर महसूस हो रही थी। लेकिन 2019 के बाद शनै शनै निराशा दूर होने लगी और सत्ता के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था वह भ्रम दूर हो रहा है।

लोहिया जी का स्मरण करने का कारण यह है कि जब दृढ़ता 5 जो देश का भविष्य है उसने शिक्षा की दुर्दशा के विरोध में मैदान पकड़ा तब लोहियाजी का प्रेरक स्लोगन चरितार्थ होते प्रत्यक्ष दिखाई दिया। जब सड़क खामोश होती है तब संसद आवारा हो जाती है। युवा नेतृत्व में सड़क को गर्म किया। युवाओं के आंदोलन के कारण सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को ऊर्जा मिली।

सन 2914 के बाद लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका पर भी जब पक्षपात का आरोप लगने लगा तब पक्षपात पूर्ण न्याय के विरुद्ध देश का अभिभाषक भी मैदान में आ गया।

सांदीपनि विद्यालयों में बस किराए का प्रस्ताव टला

भोपाल। सांदीपनि विद्यालयों में चलने वाली बसों का किराया तय करने का अधिकार कलेक्टरों को देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आने से पहले टल गया। स्कूल शिक्षा विभाग इन बसों का किराया तय करने की तैयारी में था जिसका असर सीधे तौर पर बच्चों के अभिभावकों की जेब पर पड़ता। आज होने वाली कैबिनेट में यह प्रस्ताव आने की चर्चा थी कि स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के तहत कलेक्टरों को अपने जिले में संचालित सांदीपनि विद्यालयों की बसों का किराया तय करने और अभिभावकों से वसूली का अधिकार दिया जा सकता है लेकिन कैबिनेट में यह प्रस्ताव आने से पहले टाल दिया गया। कैबिनेट बैठक में मैहर, पांढुर्णा, निवाड़ी और मऊगंज जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय खोलने तथा जिला स्तर पर पद सृजित करने के प्रस्ताव पर भी आने वाला था लेकिन इसे भी टाल दिया गया। आज हुई कैबिनेट में 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान की प्रगति और कार्यों की समीक्षा पर ही फोकस रहा। मुख्यमंत्री ने बाद में इसकी जानकारी खुद दी है।

प्रदेश में बिजली संकट, ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे तक की कटौती

कोयले की कमी से थर्मल प्लांटों का उत्पादन प्रभावित, कम बारिश से जलविद्युत पर भी असर

भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली संकट गहराने से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रमुख शहरों को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के बड़े हिस्से में दो से आठ घंटे तक बिजली कटौती किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे किसानों, व्यापारियों और आम लोगों में नाराजगी है।

कई जगह लोग बिजली उपकेंद्रों पर पहुंचकर आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों को भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर करीब 15 से 20 विधायकों ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। विधायकों ने फसलों को नुकसान होने और दुर्गा उत्सव के दौरान बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिजली संकट के चलते राज्यमंत्री करण सिंह वर्मा, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर और महिदपुर विधायक दिनेश जैन बोस को आमजनता के विरोध का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यमंत्री गौतम टेटवाल को वीडियो जारी कर बताना पड़ गया कि उन्होंने बिजली आपूर्ति के संबंध में बिजली कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की है।

बढ़ती मांग और कोयले की कमी प्रमुख वजह



इस संबंध में ऊर्जा विभाग का कहना है, कि पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश में बिजली की मांग करीब 12 हजार मेगावाट थी, जो इस वर्ष बढ़कर 16 हजार मेगावाट तक पहुंच गई है। दूसरी ओर, कोयले की कमी और तकनीकी खराबी के कारण कई बिजली संयंत्र पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। खरगोन, बिरसिंहपुर, विंध्याचल और आरकेएम पावर प्लांट की 800 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां तकनीकी खराबी के कारण बंद बताई गई हैं। प्रदेश में करीब 25 हजार मेगावाट बिजली उपलब्धता का दावा किया जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि संकट के समय बिजली खरीद समझौते (पीपीए) अपेक्षित मदद नहीं कर पा रहे हैं।

जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा पर भी असर

कम बारिश के कारण इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर और गांधीसागर जैसे जलविद्युत संयंत्रों से मिलने वाली लगभग 1,285 मेगावाट बिजली प्रभावित हुई है। वहीं, सौर ऊर्जा से दिन में करीब पांच हजार मेगावाट बिजली मिलने के बावजूद रात में इसका उत्पादन शून्य हो जाता है। बैटरी भंडारण और पंप स्टोरेज जैसी सुविधाओं की कमी इस समस्या को बढ़ाती है। प्रदेश में 2,800 मेगावाट क्षमता वाली पवन ऊर्जा परियोजनाओं से भी रात में हवा की अनुकूल गति नहीं होने के कारण महज 250 से 300 मेगावाट बिजली मिलने की बात कही गई है।

बढ़ती गर्मी और सिंचाई ने बढ़ाया दबाव

औसत तापमान में बढ़ोतरी के साथ बिजली की मांग बढ़ी है। मालवा समेत कई क्षेत्रों में कम बारिश के कारण किसानों को फसल बचाने के लिए सिंचाई पंप चलाने पड़ रहे हैं। इससे बिजली की खपत बढ़ गई है। दूसरी ओर, पावर एक्सचेंज में बिजली की कीमत 10 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंचने से महंगी बिजली खरीदना भी चुनौती बन गया है। इन परिस्थितियों में प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट ने लोगों की परेशानी और सरकार के सामने आपूर्ति बनाए रखने की चुनौती बढ़ा दी है।

मप्र में आबादी के मुकाबले 45 हजार जवान कम

भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारियों के बीच सबसे बड़ी चुनौती केवल रिक्त पद भरने की नहीं, बल्कि बढ़ती आबादी के अनुपात में पुलिस बल का विस्तार करने की भी है। प्रदेश में मौजूदा आबादी की जरूरत के हिसाब से करीब 45 हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की आवश्यकता बताई जा रही है। ऐसे में अगले तीन वर्षों में 22,500 आरक्षकों की भर्ती का लक्ष्य भी पुलिस बल की पूरी कमी दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं दिखता। सवाल यह है कि भर्ती के साथ नए पदों के सृजन की दिशा में सरकार कितनी तेजी से कदम उठाती है। प्रदेश में फिलहाल प्रति एक लाख आबादी पर औसतन 121.76 पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 143 है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों के 197 पद स्वीकृत हैं। इससे स्पष्ट है कि पुलिस बल की उपलब्धता और आबादी के अनुपात में जरूरत के बीच अंतर बना हुआ है। इसका असर गश्त, अपराधों की रोकथाम, कानून-व्यवस्था और आपराधिक मामलों की विवेचना जैसे कामों पर पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अगले तीन वर्षों में आरक्षकों के 22,500 पदों पर भर्ती की घोषणा कर चुके हैं। फिलहाल 9,662 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यह पहल पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन करीब 45 हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की जरूरत के आकलन के सामने भर्ती की मौजूदा योजना से आगे की रणनीति भी जरूरी होगी।

नशीले कफ सिरप का सप्लायर पकड़ाया

भोपाल। नशीले कफ सिरप की अवैध सप्लाई के मामले में फरार आरोपी अभिषेक निगम को देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी 30 मई 2026 को भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र के पटेल सिटी में पकड़ी गई नशीले कफ सिरप की फैक्ट्री के मामले में फरार था। उस पर 20 हजार का इनाम घोषित था। एसटीएफ उसे ट्रांजिट वारंट पर मध्यप्रदेश लेकर आई है। फिलहाल पुलिस रिमांड पर उससे पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ के मुताबिक, 30 मई को पटेल सिटी, गांधीनगर स्थित फैक्ट्री पर कार्रवाई के दौरान कोडीनयुक्त कफ सिरप की 74,104 बोतलें बरामद की गई थीं। इनमें ऑनरेक्स और ऑफकफ ब्रांड के सिरप शामिल थे। जांच में सामने आया कि अभिषेक निगम कथित तौर पर राहुल कुशवाह और सागर निवासी सीटी जैन के साथ मिलकर इन सिरप की नशे के लिए अवैध सप्लाई करता था।

अंतिम सप्ताह में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 और 2026 के आएंगे परिणाम

भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 और 2026 के परिणाम जारी को लेकर समयावधि निर्धारित की है। दोनों परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। आयोग ने अगले कुछ दिनों में कॉपियों की जांच पूरी कर परिणाम देने की व्यवस्था की है। पहले राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद 10 से 15 दिनों के भीतर 2026 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा। मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आयोग की योजना नवंबर में साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करने की है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों परीक्षाओं के साक्षात्कार अगले दो महीनों के भीतर पूरे करवाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे चयन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन जबलपुर हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद अगस्त के दूसरे सप्ताह में किया गया था। परीक्षा में 4224 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए।

अवैध खनन पर डिजिटल पहरा, अप्रैल से सख्त होगी व्यवस्था

भोपाल। मध्यप्रदेश में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर लगाम कसने के लिए सरकार निगरानी व्यवस्था को सख्त करने जा रही है। खनिज परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन पर माइनिंग टैग लगाना अनिवार्य होगा। खनिज विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को एक माह के भीतर शत-प्रतिशत वाहनों पर टैग लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से खनिज परिवहन की निगरानी डिजिटल माध्यम से करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए 25 जिलों में अप्रैल से एआई आधारित मानव रहित ई-चेकगेट की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत 40 ई-चेकगेट स्थापित किए जा चुके हैं। अब माइनिंग टैग के माध्यम से वाहनों की पहचान और परिवहन संबंधी जानकारी की निगरानी को और प्रभावी बनाने की तैयारी है।

टैग खराब हुआ तो

खनिज परिवहन पर रोक

नई व्यवस्था में माइनिंग टैग की स्थिति को लेकर भी सख्ती रखी गई है। यदि किसी वाहन का टैग क्षतिग्रस्त होता है, तो उस वाहन से खनिज परिवहन प्रतिबंधित किया जा सकेगा। साथ ही ई-खनिज पोर्टल पर वाहन का पंजीयन निरस्त करने का प्रावधान भी बताया गया है। इससे टैग में छेड़छाड़ या उसके खराब होने की स्थिति में संबंधित वाहन की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।

पांच लाख से ज्यादा वाहनों पर लगेगा टैग

प्रदेश में खनिज परिवहन के लिए पांच लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इन सभी वाहनों पर माइनिंग टैग लगाने की जिम्मेदारी तय समयसीमा में पूरी करना खनिज विभाग और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्रत्येक टैग के लिए 138 रुपए के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस तरह टैग लगाने पर वाहन संचालकों को निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा।

महाराष्ट्र मॉडल से एमपी में एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले सात इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधन जुटाने की है। एक साथ इतने बड़े सड़क प्रोजेक्ट शुरू करने पर राज्य के बजट पर भारी दबाव पड़ सकता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) महाराष्ट्र के मॉडल पर परियोजना आधारित कंपनियां बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत बड़े एक्सप्रेस-वे और हाईवे के लिए अलग-अलग स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) गठित किए जा सकेंगे, जो परियोजना के नाम पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सीधे कर्ज जुटा सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण के लिए पैसा जुटाना नहीं, बल्कि परियोजना की वित्तीय जिम्मेदारियों, निर्माण अनुबंधों, टोल वसूली और रखरखाव को एक अलग ढांचे में संचालित करना है। इससे सरकार को सभी परियोजनाओं के लिए सीधे बजट से राशि उपलब्ध कराने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, इस मॉडल की सफलता सड़क से होने वाली संभावित कमाई, कर्ज की शर्तों और परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। प्रदेश में प्रस्तावित सात इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण पर 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इतनी बड़ी राशि का इंतजाम राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार को सड़क परियोजनाओं के लिए भारी बजटीय आवंटन करना पड़ा, तो दूसरे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर भी असर पड़ सकता है।



एलमेफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज का स्पष्टीकरण: 'बिना नमूने के परीक्षण रिपोर्ट बनना हमारी प्रक्रिया में संभव नहीं'

इंदौर। दिनांक 29 सितंबर 2026 को एक समाचार पत्र (दैनिक भास्कर) में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में एलमेफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज प्रा. लि., इंदौर ने अपना पक्ष रखा है। एलमेफ एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला है।संस्था केसंचालक श्री प्रतीक शर्मा ने बताया कि समाचार में उल्लेख है कि संवाददाता ने लैब मालिक के रूप में उनसे संपर्क किया था। उन्होंने विनम्रतापूर्वक स्पष्ट किया कि इस विषय में उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। उस अवधि में वे कार्यवश दिल्ली में थे, इंदौर में नहीं।तोह न फ़ोन पर न ही पर्सनली। श्री शर्मा ने कहा कि समाचार को गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन ने इसे एलमेफ कंपनी की निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिकायत के रूप में दर्ज किया। इसके बाद संस्था की मानक कार्यप्रणाली के अनुसार प्रारंभ से मूल कारण विश्लेषण (रूट कॉज़ एनालिसिस) और सभी अभिलेखों की विस्तृत जाँच की गई। जाँच में निम्न अभिलेख देखे गए:

आगंतुक पंजिका (विजिटर बुक): नमूना जमा करने या किसी से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रविष्टि इसमें होती है।टेस्ट रिपोर्ट ELMEF/26/09/252/0003/EL-0001 का सैम्पलदिनांक :-09/09/2026 को लैब में रिसीव हुआ ।

नमूना प्राप्ति पंजिका: प्रयोगशाला में आने वाला प्रत्येक नमूना इसमें दर्ज किया जाता है। टेस्ट रिपोर्ट ELMEF/26/09/252/0003/EL-0001 का सैम्पलदिनांक :-09/09/2026 को लॉगिन किया।

नमूना कोडिंग: दर्ज होने के बाद नमूने को एक विशिष्ट कोड देकर तकनीकी टीम को परीक्षण के लिए भेजा जाता है।कोड जो की ELMEF/26/09/252/0003 दिया गया

परीक्षण अभिलेख: परीक्षण संबंधित भारतीय मानक (IS) और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है, और उसके सभी परिणाम दर्ज किए जाते हैं। (ELMEF/26/09/252/0003/EL-0001का परिक्षण भी किये गया) ।

रिपोर्ट निर्माण: परीक्षण परिणामों के आधार पर ही रिपोर्ट का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनता है। अंतिम रिपोर्ट भुगतान प्राप्त होने और ग्राहक की स्वीकृति मिलने के बाद ही जारी की जाती है। (Rs. 5000/- 1:16pm को प्राप्त हुआ, पेमेंट प्राप्त होने के बाद 4:49PMड्राफ्ट दिया और शाम 6:38PM को टेस्ट रिपोर्ट दे दी गयी) ।

प्रबंधन की जाँच में ये सभी अभिलेख व्यवस्थित और पूर्ण पाए गए। अभिलेखों के अनुसार संबंधित नमूना प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ था, उसका विधिवत परीक्षण हुआ था, और उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी।जिसकी सारे एविडेंस जैसे कीआगंतुक पंजिका (विजिटर बुक),नमूना प्राप्ति पंजिका,नमूना कोडिंग फॉर्म,डिस्पोजल स्लिपें (दिनांक :- 26/09/2026) श्री शर्मा द्वारा दिए गए।

और जिस सैंपल का परिक्षण हुआउस तरीके के सैंपल (कंडक्टर), वो एक घंटे के अंदर टेस्ट हो सकता है और रिपोर्ट बन सकती है, बहुत लोग ऐसे सैंपल हथों हाथ 2 घंटे में रिपोर्ट लेके भी जाते हैं ।

टेस्ट रिपोर्ट बनने के बाद सैंपल डिस्पोजल रूम में रखा जाता है, एंड वो सैंपल कुछ दिन संभाल कर भी रखता जाता है, उतनेदिन भी टेस्ट रिपोर्ट में मेंशन करने जाते हैं, और अगर रिपोर्ट में कुछ चेंज या अमेंड करवाना होता है तो,क्लाइंट कितने दिनों के अंदर करवा सकता है उतनेदिन भी टेस्ट रिपोर्ट में दिया होता है

श्री शर्मा ने बताया कि संस्था में कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। नमूना प्राप्त करने का कार्य, ग्राहक से भुगतान और पचाचार का कार्य, और तकनीकी परीक्षण का कार्य अलग-अलग विभाग और अलग-अलग कर्मचारी करते हैं। वाणिज्यिक विभाग का परीक्षण कार्य से कोई संबंध नहीं होता। नमूने की प्राप्ति से लेकर उसके निपटान तक की पूरी प्रक्रिया अभिलेखित होती है और सीसीटीवी निगरानी में होती है। इसमें अनेक व्यक्तियों की भूमिका होती है, इसलिए किसी एक व्यक्ति के स्तर पर बिना नमूने के रिपोर्ट बना देना संभव नहीं है।

उन्होंने तृतीय-पक्ष प्रयोगशाला की भूमिका भी स्पष्ट की। प्रयोगशाला का दायित्व उस नमूने तक सीमित होता है जो उसे परीक्षण के लिए सौंपा जाता है। ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस नमूने का निष्पक्ष परीक्षण करना और सही रिपोर्ट देना प्रयोगशाला का कार्य है। नमूना कहाँ से लाया गया, और बाद में कार्यस्थल पर वही सामग्री उपयोग हुई या नहीं, यह प्रयोगशाला के नियंत्रण में नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति घी का नमूना जाँच के लिए लाता है, तो प्रयोगशाला यह नहीं जान सकती कि वह नमूना बाज़ार से लिया गया है या घर में बनाया गया है। प्रयोगशाला केवल उस नमूने की गुणवत्ता की जाँच करती है और परिणाम के अनुसार रिपोर्ट देती है। परंतु नमूना आए बिना कोई रिपोर्ट नहीं बन सकती। यही सिद्धांत विद्युत उपकरणों के परीक्षण पर भी लागू होता है।

श्री शर्मा ने कहा कि मीडिया समाज में पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संस्था उसका पूरा सम्मान करती है। फिर भी इस समाचार से संस्था की प्रतिष्ठा और व्यवसाय पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एलमेफ ने वर्षों की मेहनत से गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर अपनी पहचान बनाई है।

प्रतीक शर्मा (संचालक)
एलमेफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज प्रा. लि.
आरएच-8, काउंटी वॉक, झलारिया, इंदौर (म.प्र.) - 452016

कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की कुर्सी पर परफॉर्मेंस का पहरा

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस में अब संगठनात्मक पदों पर बने रहने के लिए राजनीतिक अनुभव के साथ कामकाज का हिसाब देना भी जरूरी होगा। पार्टी जिला स्तर पर नेतृत्व की समीक्षा कर रही है। नवरात्र के बाद छह जिला अध्यक्षों को बदलने की संभावना इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इसके जरिए पार्टी उन जिलों में नई ऊर्जा लाने की कोशिश करेगी, जहां संगठन की गतिविधियां अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाई हैं। संभावित बदलाव में डिंडौरी के ओमकार सिंह मरकाम और सतना के सिद्धार्थ कुशवाह के नाम चर्चा में हैं। आलीराजपुर में जिला अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद नए चेहरे की नियुक्ति की जानी है। हालांकि, अन्य जिलों के नाम और बदलाव का अंतिम निर्णय अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश की 71 शहर और ग्रामीण जिला इकाइयों में अध्यक्ष नियुक्त किए थे। इस प्रक्रिया में पार्टी ने पूर्व मंत्रियों और विधायकों को भी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी। प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह और ओमकार सिंह मरकाम जैसे नेताओं को जिला स्तर पर जिम्मेदारी देने के पीछे उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ उठाने की रणनीति थी। अब पार्टी के सामने चुनौती यह है कि राजनीतिक अनुभव को जमीनी सक्रियता में कितना बदला जा सका। जिला अध्यक्षों से संगठन का विस्तार करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और स्थानीय मुद्दों पर पार्टी की मौजूदगी मजबूत करने की अपेक्षा है। ऐसे में संभावित फेरबदल को केवल पद बदलने की कवायद के बजाय संगठनात्मक जवाबदेही तय करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जिला अध्यक्षों में बदलाव की प्रक्रिया नवरात्र से पहले आगे बढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन और अन्य संगठनात्मक गतिविधियों के कारण निर्णय टल गया। अब नवरात्र के बाद पार्टी नेतृत्व इस पर फैसला ले सकता है। इस कवायद का असर केवल छह जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। जिन नेताओं को जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा, उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलने से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। हालांकि, नए अध्यक्षों के चयन में किन मानकों को प्राथमिकता मिलेगी, यह अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।



कांग्रेस जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारियों में विधानसभा चुनाव से लगभग एक वर्ष पहले अक्टूबर-नवंबर 2027 में फिर बदलाव कर सकती है। पार्टी की योजना उन नेताओं को संगठनात्मक पदों से मुक्त करने की है, जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है।

स्वामी मेसर्स एसोसिएटेड प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (एम.पी.) प्रा.लि. इंदौर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मोनिका सेठ द्वारा 17, न्यू देवास रोड (संजय गांधी मार्ग) इंदौर से मुद्रित एवं 5, प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित संपादक-मोनिका सेठ,
फोन नं. 3551753, 2434701, 2544433, समाचार पत्र से प्रकाशित समाचार के लिए सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा। समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार*